■(b) INSAT-IB and INSAT-ID are providing operational services in the areas of TV networking and broadcasting, Telephone Telegraphy communications, meteorological imaging and data dissemination, disaster warning services, emergency communications, rural/remote are a communications and radio networking. IRS-1A is used for providing information for management of natural resources and environment.

(c) The use of INSAT-1 satellites (INSAT) has been instrumental in rapid expans'on of TV coverage in the country with more than 520 TV stations and 35,000 direct reception centres served by INSAT Network. INSAT is used for broadcasting educational programmes under the UGC Programme. The telecommunication service with 106 earth stations covering 119 telecom routes are served by INSAT. These are also used for conn-ecting remote areas and offshore islands with the rest of the country: and a satellite based rural telegraphy service has been started on an experimental basis in the north-eastern region. INSAT has also been providing continuous pictures of clouds over the Indian Ocean region which is used for meteorological studies and weather prediction. INSAT also serves for quick and timely dissemination of meteorological data collected from various land and ocean (based plat-forms in Indian region. The disaster warning system served by INSAT with about 100 platforms off the eastern coast, have been responsible for issu, ing timely warnings about cyclones etc., and these have enabled advance actions for evacuation and thereby saving precious lives during cyclones in the past.

The information generated from IRS-1A satellite are being used for ground water potential zone mapping in 442 districts in the country in a record time, which has increased the success rate to about 90 per cent as compared to about 40 per cent when conventional methods alone are used. IRS imageries have been used to pre pare wasteland maps in as many as 146 districts from which data base of wasteland at village level could be .generated for the first time in the country. Satellite remote sensing data has also been responsible for accelerating the forest monitoring methodology and biennial mapping of the country's forest resources (by the Forest Survey of India (FSI) has now been made possible. Satellite data has also been very useful in agricultural drought assessment; and already drought assessment bulletins are being generated regularly on a fortnightly basis covering 246 drought-prone districts and these provide useful information. for the district authorities to take necessary steps. In view of the availability of satellite data, it is possible to generate in almost near rea] time, the flood area maps and make flood damage assessments. In the area of msrine fisheries also, the use of information provided by the satellites had resulted in identifying zones which can yeild increased fish catch. For major crops, like wheat, rice, sorghum and groundnut, large area crop acreage and production estimations are being carried out using the satellite pictures. In addition to the above, satellite data is also being used for a number of other natural resources related studies like soil resources mapping, land use, soil salinity and alkalinity map-pine, estimat'o-n of the flow of water into reservoirs, wild life habitat mapping and for deriving integrated approaches for combating drought.

उच्च शिक्षा पर वित्तीय राज सहायता में कमी

71. **श्री बलराम सिंह यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1990 के "स्टेटसमैन" में "एक्सपर्टस फोर कट इन सबसिडि" (विशेषज्ञ

राज सहायता में कमी करने के पक्ष में) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्च शिक्षा पर वित्तीय राज सहायता में कमी करने की विशेषज्ञों की सलाह पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) उच्च शिक्षा को स्व-वित्त पोषित बनाने की जरूरत के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है । सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

तकनीकी शिक्षा के लिये फीस बढ़ाने का प्रस्ताव

72. **श्री बलराम सिंह यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने राज्य सरकारों द्वारा तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रों से ली जा रही फीस बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा फीस में वृद्धि करने का सुझाव देने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कार्यकारी समिति ने यह नोट किया है कि तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में व्याप्त वर्तमान शुल्क ढांचा अधिकांश रूप से पूर्व-स्वतंत्रता स्तर पर है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इस समय लगभग 162 अनुमोदित इंजीनियरी कालेज तथा 500 पालिटेक्निक हैं । एक इंजीनियर और डिप्लोमाधारी के प्रशिक्षण का अनुमानित आवर्ती व्यय प्रति छात्र प्रतिवर्ष 2000 रु० और 8000 रु० है । एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम और वांछनीय अनावर्ती व्यय क्रमश: 6.65 करोड़ रु० और 7.59 करोड़ रु० है । एक पालिटेनक को स्थापित करने के लिए तदनुरूपी राशि क्रमश: 3.87 करोड़ रु० और 4.91 करोड़ रु० है । आठवीं योजना के दौरान तकनीकी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित राशि 3000 करोड़ रु० का अनुमान है । समिति का यह विचार था कि तकनीकी संस्थाओं में शुल्कों को और अधिक वास्तविक स्तर पर लाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वसूल की जाने वाली फीसों और प्रशिक्षण की वास्तविक लागत के बीच कुछ उचित सम्पर्क हो । तथापि, कठिनाई यह है कि एक औसत भारतीय की अदायगी क्षमता सीमित है और यदि शुल्कों में पर्याप्त वृद्धि की जाती है तो छात्रों के लिए कुछ ऋण संबंधी प्रबन्ध करने होंगे जिन्हें रोजगार मिलने के बाद वे उसे कुछ समय के अन्दर लौटा सकें । यह मेधावी छात्रों को अवसर प्रदान करेगा और न केवल उनको जो अधिक शुल्क अदा कर सकते हैं ।

उच्च शिक्षा में छात्रों पर किये जा रहे खर्च में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

73. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च तकनीकी तथा शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों पर खर्च करने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार कर रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में प्रत्येक छात्र पर लगभग 1 लाख रुपया खर्च किया जाता है जबकि ट्यूशन फीस के रूप में उस से केवल 5000 रुपये वसूल किए जाते हैं ;